में रखने, विशेषज्ञ न्यायपीठ गठत करने, शीघ्र निपटारे की अपेक्षा रखने वाल मामले को पूर्विकता देने आदि जैसे विभिन्न उपाय कर रहे है । बकाया मामला विषयक समिति द्वारा, जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों को समस्या की जांच की थी, की गई विभिन्न सिफारिशें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई है ।

Percentage of educated unemployment to total unemployment

2392. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the percentage of educated unemployment to the total unemployment as on date;

(b) whether it is a fact that there is a paucity of vocational training institutes and schools in India; and

(c) if so, what are the plans to reduce the shortage of such infrastructure?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) On the basis of the results of the last comprehensive survey on employment and unemployment conducted by the Natoinal Sample Survey Organisation in 1987-88, it is estimated that educated unemployed constitute around 40 per cent of the total unemployed.

(d) and (c) There may be a shortage of the voaction al training institutes and schools in the country and the facilities available therein may not be sufficient for the existing and emerging menpower requirements. However, there has been continuous increase in the number of ITIs and their seating capacity. The Directorate General of- Employment and Training, Ministry of Labour, is implementing a comprehensive Vocational Training Project assisted by World Bank since 1989-90 with the aim of strengthening and upgrading the existing infrastructure to meet the demand of skilled craftmen. The Government has also accorded high priority to vocationalisaton of secondary education. Since 1988, a Centrally Sponsored Scheme has been introduced under which 100 per cent assistance is given to States to start vocational education programme.

In addition to vocational courses at + 2 level (Higher Seceondary, the Central Government proposes to start non-formal, flexible and need based programmes of vocational education to cater to t he needs of women, rural areas and deprived sections of society.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास आयोग की स्थापना किया जाना

3293. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक विकास आयोग बनाने का विचार रखती है ; और

(ख) यदिजहां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) किसी एक विशेष क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं/कार्यक्रमों में किया गया केन्द्रीय निवेश

3284. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आम तौर पर उन क्षेत्रों के कार्यक्रमों/परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश किया जाता है जहां आवश्यक वित्तीय संसाधन इष्टतम स्तर तक उपलब्ध होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश कर उन कार्यक्रमों परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या है, जिनमें पिछले वर्ष के दौरान केन्द्रीय निवेश किया गया था और ये कार्यक्रम/परियोजनाएं किन-किन क्षेत्रों और सेवाओं से संबंधित थे ; और

(ग) इन्हीं कारकों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय सहायता का निर्धारण विभिन्न कारकों के द्वारा किया जाता है । जैसे कि तकनीकी-आर्थिक उपादेयता, वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ आधारभूत संरचना और कच्चे माल की उपलब्धता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Development schemes of West Bengal

3295. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of West Bengal have sent some development schemes to Planning Commission during the last two years for approval;

(b) if so, what are the details and locations of these schemes; and

(c) what action has been taken on each such scheme by the Planning Commission?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINSITRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHR(I H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A Statement is enclosed.

Statement

S. No.	Particulars	Remarks
1.	Project report for Sagardihi TPS Stage-I to be installed in Murshidabad district of West Bengal.	The Project is under examination in the Central Electriicity Authority.
2.	Bel Bali Drainage Scheme with estimated cost of Rs. 214.80 lakhs.	The State Government is to provide some clarifications.
3.	Four bank protection schemes in Murshidabad district of West Bengal.	The schemes have been accorded investment clearance by the Planning Commission.